

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,  
लोक निर्माण विभाग,  
30प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक 23 दिसम्बर, 2020

**विषय:-** मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से आच्छादित जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद में चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग (गंग नहर की दांयी पटरी) के नव निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-4168नि/116-01नि/19-2020, दिनांक 18-03-2020 एवं पत्र संख्या-750नि0/116-01नि0/19-20, दिनांक 09-09-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा (कम्प्यूटर संख्या-जीएच11 वाई00154, घोषणा संख्या-वाई0ए0एन0-17/2018, घोषणा दिनांक 28-05-2018) से आच्छादित जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद में चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग (गंग नहर की दांयी पटरी) के नव निर्माण कार्य की आंकलित लागत रु0 62874.26 लाख (रुपये छः अरब अट्ठाईस करोड़ चौहत्तर लाख छब्बीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में लागत के सापेक्ष कुल रु0 10000.00 लाख (रुपया एक अरब मात्र) व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रुपये लाख में)

| क्र० सं० | जनपद                         | कार्य का विवरण                                                                                                      | स्वीकृत लागत | अवमुक्त धनराशि |
|----------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 1        | 2                            | 3                                                                                                                   | 4            | 5              |
| 1        | मुजफ्फर नगर, मेरठ, गाजियाबाद | जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ एवं गाजियाबाद में चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग (गंग नहर की दांयी पटरी) के नव निर्माण का कार्य। | 62874.26     | 10000.00       |

- (1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
- (2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- (3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (4) स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।
- (5) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25-01-2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। लेखा शीर्षक 1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्ति-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में जमा की जायेगी।
- (6) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
- (7) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।
- (8) व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (9) प्रश्नगत परियोजना कार्य हेतु नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।
- (10) प्रायोजना में यूटिलिटी शिफ्टिंग के अन्तर्गत विद्युत विभाग के विद्युत लाईन, बिजली के खम्भे की शिफ्टिंग का कार्य की लागत वास्तविकता के आधार पर सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त देय होगी।
- (11) वन विभाग सम्बन्धी कार्य हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन के अनुसार प्रस्तावित लागत के यथावत सम्मिलित कर लिया गया है परन्तु निर्माण के समय वास्तविकता के आधार पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए कार्यवाही करेंगे।
- (12) प्रायोजना में जनपद मुजफ्फरनगर में 1.05 हे० भूमि का क्रय किया जाना प्रस्तावित है, इस हेतु जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर द्वारा अनुमन्य सर्किल दरों को प्रयुक्त किया गया है। भूमि अध्याप्ति न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय।
- (13) जनपद मेरठ में जल विद्युत निगम के भवन (170.35 व०मी०) हस्तान्तरण हेतु लागत ₹० 28.67 लाख प्रस्तावित की गयी है। इस धनराशि का व्यय न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय।
- (14) प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो।
- (15) प्रस्तावित कार्यों की द्विगुणित (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है और इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।



- (16) वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-16-गंग नहर की दांयी पटरी का निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढीकरण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-8-2539/दस-2020, दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,  
(गिरिजेश कुमार त्यागी)  
विशेष सचिव।

संख्या-372/2020/182(आ)(1)/23-11-2020-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम्/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम्/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
- 5- वित्त नियंत्रक लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
- 6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
- 7- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 8- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु0-8/वित्त आय-व्ययक अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
- 9- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
- 10- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 11- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
- 12- डेटा सेल, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
(गिरिजेश कुमार त्यागी)  
विशेष सचिव।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।